मुख्यमंत्री ने Safe and Responsible Migration Initiative (SRMI) का किया शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

16 दिसिंबर, 2021 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में प्रवासी मज़दूरों के पलायन को सुरक्षित बनाने हेतु बनाई गई पॉलिसी **Safe and Responsible Migration Initiative (SRMI)** का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- वर्तमान में **Safe and Responsible Migration Initiative (SRMI)** पायलट प्रोजेक्ट के तहत दुमका, पश्चिमी सिंहभूम तथा गुमला के श्रमिकों के पलायन को ध्यान में रखकर नीति बनाई गई है।
- इन तीन ज़िलों से दिल्ली, केरल और लेह-लद्दाख इत्यादि जगहों में रोज़गार के लिये गए प्रवासी श्रमिकों का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। इन सभी राज्यों से समन्वय स्थापित कर प्रवासी श्रमिकों के सामाजिक, आर्थिक और कानूनी हक सुनिश्चित किये जाएंगे।
- प्रवासी श्रमिकों का किसी भी प्रकार से शोषण न हो सके, इस निमित्त नियम बनाए गए हैं। शुरुआती दौर में इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद व्यवस्था के दायरे को और बड़ा बनाया जा सकेगा।
- इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने BOCW के अंतर्गत विवाह सहायता योजना, मातृत्व प्रसुविधा योजना, अंत्येष्टि सहायता योजना, झारखंड निर्माण कर्मकार मृत्यु/दुर्घटना सहायता योजना एवं मेधावी पुत्र-पुत्री छात्रवृत्ति सहायता योजनाओं का लाभ सभागार में उपस्थित लाभुकों के बीच वितरित किया।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर किसी प्रवासी श्रमिक की मृत्यु होती है तो राज्य सरकार उसके दिवंगत शरीर को वापस उसके घर लाने की व्यवस्था करेगी तथा अंत्येष्टि का पूरा खर्चा राज्य सरकार ही वहन करेगी। इसके लिये सभी ज़िलों में कॉरपस फंड की व्यवस्था की जा रही है।
- राज्य के प्रवासी मज़दूरों को संरक्षित करने के लिये सरकार द्वारा ई-श्रम पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल के तहत प्रवासी श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, ताकि विपत्ति के समय राज्य सरकार उन्हें तत्काल मदद पहुँचा सके।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इत्यादि राज्यों से रेस्क्यू कर लाई गई युवतियों एवं महिलाओं को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रोज़गार देने का काम राज्य सरकार ने हाल के दिनों में किया है। 2 हज़ार नियुक्ति पत्र टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बाँटे गए थे, जिनमें 80% महिलाएँ थीं।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/safe-and-responsible-migration-initiative